भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2028

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजमार्गों का निर्माण

2028. श्री अतुल गर्ग:

श्री अरुण भारती:

श्रीमती शांभवी:

डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

श्री राजेश वर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजमार्ग निर्माण की गति से देश में संपर्क सुविधा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा आम नागरिकों के यात्रा समय में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान विशेषरूप से गाजियाबाद, जमुई, समस्तीपुर, राजमुंदरी और खगड़िया संसदीय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए और जनता के लिए खोले गए प्रवेश-नियंत्रित एक्सप्रेसवे तथा राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवसंरचना पहल के अंतर्गत दूरस्थ ग्रामीण कृषि क्षेत्रों को प्रमुख शहरी बाजारों से जोड़ा गया है, जिससे लघु किसानों की आय में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रमुख सड़क निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए सृजित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आम यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक पचास किलोमीटर पर किफायती फूड कोर्ट तथा स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों सहित आधुनिक मार्ग-सुविधाओं के विकास हेतु नियोजित आगामी कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी, हाँ। भारतमाला परियोजना के तहत परियोजना के कार्यान्वयन ने आर्थिक केंद्रों, बंदरगाहों, औद्योगिक समूहों, सीमावर्ती क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों के बीच संपर्कता में सुधार करके राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को काफी सुदृढ़ किया है। कार्यक्रम के तहत प्रवेश-नियंत्रित एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर के विकास की परिकल्पना प्रमुख आर्थिक केंद्रों और प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा के समय को 40-50% तक कम करने के साथ-साथ रसद (लॉजिस्टिक) दक्षता बढ़ाने, वाहन संचालन लागत को कम करने और यात्रियों के लिए सुरक्षित और शीघ्र यात्रा प्रदान करने के लिए की गई है। कुल मिलाकर, कार्यक्रम ने देश भर में संपर्कता और गतिशीलता (मोबिलिटी) में काफी सुधार किया है।

(ख) गाजियाबाद और जमुई, समस्तीपुर, राजमुंदरी और खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में प्रवेश-नियंत्रित राजमार्ग/एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई क्रमशः 10,660 किमी और 9,361 किमी है।

(ग) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बैंगलोर द्वारा भारतमाला परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आर्थिक रूप से, घरेलू आय और व्यय में वृद्धि हुई है। लागत में कमी के साथ रसद (लॉजिस्टिक) दक्षता में सुधार हुआ है। व्यवसायों को बाजारों और कारखानों तक बेहतर सुलभता से लाभ हुआ है। सामाजिक रूप से, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक यात्रा का समय कम हो गया है, जिससे पहुंच आसान हुई है। कुल मिलाकर, अध्ययन से पता चलता है कि भारतमाला परियोजना ने सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(घ) आईआईटी कानपुर के अध्ययन के अनुसार, राजमार्ग के प्रत्येक लेन-किलोमीटर के विकास से लगभग 4,500 प्रत्यक्ष रोजगार के कार्य-दिवस और लगभग 5,600 अप्रत्यक्ष रोजगार के कार्य-दिवस उत्पन्न होते हैं। तदनुसार, भारतमाला परियोजना से देश भर में भारी संख्या में प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हुए हैं।

(ङ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 40-60 किलोमीटर के अंतराल पर सार्वजनिक सुविधाओं जैसे भोजनालय, शौचालय, पेयजल, पार्किंग, ईंधन स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, अल्पकालिक आवास, चिकित्सा सहायता आदि प्रदान करने के लिए सड़क प्रयोक्ताओं और ट्रक चालकों के लिए मार्गस्थ सुविधाओं के विकास की परिकल्पना की है।

आज तक, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 137 डब्ल्यूएसए साइटें परिचालनरत हैं।

*****